International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 11 | Nov - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

कोयला खनन क्षेत्र में सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी आजीविका ढांचा

आकाश कुमार आनंद

शोधकर्ता
आई० आर० पी० एम० विभाग
ति० मा० भा० वि० वि० भागलपुर

संक्षेप

खनन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) ने विशेष रूप से भारत जैसे देशों में गति बढ़ा दी है जहां इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इस पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र क्षेत्रों में खनन की वास्तविक सामाजिक चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करना और यह पता लगाना है कि कोयला क्षेत्र की कंपनियां प्रभावित समुदायों के उत्थान के लिए व्यवस्थित तरीके से कैसे काम कर सकती हैं। पत्र का पहला भाग साहित्य के तीन अलग-अलग निकायों, यानी सीएसआर और कोयला खनन, क्षमता निर्माण और खनन क्षेत्रों में आजीविका सृजन से साक्ष्य खींचता है। हम सीएसआर निवेश की मदद से क्षमता निर्माण के माध्यम से आजीविका सृजन कार्य के लिए एक उपन्यास ढांचे का प्रस्ताव करने के लिए साहित्य को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। पत्र भारत के झारखंड राज्य में मुरियाडीह कोयला खदानों में क्षमता निर्माण गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन का एक जीवंत मामला भी दस्तावेज करता है और व्यापार और नीति निर्माताओं दोनों को सबक प्रदान करता है।

कीवर्ड : खनन, सीएसआर और खनन, क्षमता, निर्माण, आजीविका, सामुदायिक विकास

परिचय

खनन उद्योग देशों के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में 20 मिलियन से अधिक लोग अपने जीवनयापन के लिए खनिज संसाधन निष्कर्षण पर निर्भर हैं (जेनकिंस, 2004)। प्रागैतिहासिक काल से ही खनन सामाजिक विकास में एक आवश्यक योगदानकर्ता रहा है। खनिजों ने युगों से विशिष्ट मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें भोजन और आश्रय सुरक्षित करना, रक्षा प्रदान करना, शिकार करने की क्षमता बढ़ाना, आभूषण और मौद्रिक विनिमय की आपूर्ति करना, परिवहन, ऊष्मा और बिजली प्रणालियों को सक्षम बनाना और उद्योग को आधार प्रदान करना शामिल है (हार्टमैन, 1987)। खदानें न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करती हैं बल्कि विदेशी मुद्रा आय और कर राजस्व भी उत्पन्न करती हैं (दास और मिश्रा, 2015)। जबकि उद्योग के कई आर्थिक लाभ हैं, इसे विभिन्न पर्यावरणीय जोखिमों और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के लिए भी दोषी ठहराया जाता है इन प्रभावों में सामाजिक विघटन और विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, और विरासत और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं (डैनियलसन, 2006, केम्प, 2010, ओवेन और केम्प, 2015)। खनन गतिविधियाँ विभिन्न भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि और जल संसाधनों की गिरावट, भूगर्भीय खतरे और पारिस्थितिक परिदृश्य के विनाश (झिगुओ एट अल।, 2011) को भी जन्म देती हैं।

साहित्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि दुनिया की अधिकांश सक्रिय खदानें और अन्वेषण गतिविधियाँ पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में हैं। एक बार खनन पूरा हो जाने के बाद, देशों को पर्यावरण और आसपास के आवास पर प्रभावों को कम करने के लिए कोयला खनन स्थलों के लिए पुनर्ग्रहण योजनाओं की आवश्यकता होती है। खनन

गतिविधियों के कारण भूमि की गड़बड़ी और लोगों का विस्थापन बड़े पैमाने पर होता है (मिश्रा, 2009, ओवेन और केम्प, 2015, व्हिटमोर, 2006)। ये सभी मुद्दे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं कि भूमि पुनर्ग्रहण को आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों के सृजन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है और विभिन्न देशों में कई कंपनियाँ समुदाय और व्यापक रूप से लोगों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और आजीविका के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से विस्थापित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के संदर्भ में पर्यावरणीय और सामाजिक, दोनों ही मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है। साहित्य में ऐसे मामलों पर प्रकाश डाला गया है जहाँ विभिन्न देशों में इन पहलों को लागू किया गया है और इसका विवरण बाद के खंडों में प्रस्तुत किया गया है। फिर भी, मौजूदा साहित्य बहुत सीमित, विविध और विभिन्न संदर्भों में लिखा गया है, जिससे शिक्षा जगत और व्यवहार दोनों के लिए कोई भी सार्थक निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। कॉर्पोरेट प्रयासों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सामुदायिक विकास पर केंद्रित करने के लिए, यह उचित है कि अधिक केंद्रित और सार्थक आजीविका गतिविधियों में निवेश किया जाए। साहित्य में खनन क्षेत्रों में इन गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए किसी विशिष्ट विकास ढाँचे का लगभग कोई उदाहरण नहीं है और हमारा शोधपत्र इसी कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए, यह शोधपत्र तीन अलग-अलग क्षेत्रों के साहित्य की समीक्षा करके और भारत में बदलती सीएसआर व्यवस्था के संदर्भ में खनन क्षेत्रों में स्थायी ग्रामीण आजीविका के लिए एक नवीन ढाँचा प्रदान करके योगदान देता है। प्रस्तावित ढाँचे में अन्य खनन क्षेत्रों में भी अपनाए जाने की गुंजाइश और क्षमता है और यह सीएसआर ढाँचों में भी योगदान देता है।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य की समीक्षा अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर चार क्षेत्रों पर केंद्रित है, यानी खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे; स्थानीय आजीविका पर प्रभाव; सीएसआर और खनन कंपनियां, खनन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और कौशल विकास। मौजूदा साहित्य के आधार पर, हमने अनुसंधान अंतराल की पहचान करने और नियामक व्यवस्था को बदलने और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास लक्ष्यों में उभरते प्रतिमानों के संदर्भ में सीएसआर और टिकाऊ आजीविका के इस उभरते क्षेत्र में अनुसंधान दिशाएं प्रदान करने की कोशिश की है। जबकि यह पत्र वैश्विक परिप्रेक्ष्य से साहित्यिक इनपुट प्रदान करता है, यह भारतीय कोयला खनन परिदृश्यों के संदर्भ में लिखा गया है। यह पत्र भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले के मुरियाडीह कोयला खदानों में लागू एक केस स्टडी से इनपुट का भी उपयोग करता है और स्थानीय संदर्भ में आजीविका विकास और कार्यान्वयन के लिए एक उपन्यास ढांचे का प्रस्ताव करता है

कोयला खनन स्थिरता की चुनौतियाँ

खनन के चरण में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में भूमि का क्षरण शामिल है, जो शायद कोयला खनन कार्यों का सबसे गंभीर प्रभाव है। खनन परियोजनाएँ न केवल उन लोगों को प्रभावित करती हैं जिनकी ज़मीन और घर खनन के लिए छीन लिए गए हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करती हैं क्योंकि वे स्थानीय पर्यावरणीय प्रभावों से पीड़ित होते हैं, जिसमें पानी की कमी, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण, स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि शामिल हैं। भूमिगत खनन की तुलना में खुली खदानों में खनन से भूमि का क्षरण कहीं अधिक होता है (केम्प, 2010, कुमार एट अल., 2015)। भारत में बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खुली खदानों में खनन पर विशेष ज़ोर दिए जाने के कारण, खुदाई, कचरे के ढेर लगाने, कार्यशालाओं से निकलने वाले पानी, टेलिंग तालाबों के निर्माण आदि जैसी गतिविधियों के कारण भूमि के बड़े हिस्से क्षरित हो जाते हैं। भूमिगत खनन कार्यों से भूमि के धंसने की समस्या भी उत्पन्न होती है और इसके परिणामस्वरूप स्थलाकृति और जल निकासी पैटर्न में परिवर्तन होता है (एमओसी, 2005)।

सामाजिक प्रभाव विस्थापन, आजीविका की हानि और सामाजिक बहिष्कार के रूप में सामने आते हैं। स्थानीय समुदायों की आजीविका पर खनन के प्रभाव को काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। अक्सर, सारा लाभ खनन उद्योग और उसके कार्यबल को मिलता है, जिससे इलाके की बाकी आबादी वंचित रह जाती है। खदान प्रभावित समुदायों के दृष्टिकोण से, वे

अपनी जीवनशैली, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर लगातार बुरे प्रभावों का सामना कर रहे हैं (व्हिटमोर, 2006)। ये आबादी केवल लागत वहन करती है, जबकि लाभ का प्रावधान असंतुलित है (दास और मिश्रा, 2015, ओवेन और केम्प, 2015)। कोयला खनन कार्य खदान श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के भी अधीन हैं, जिनमें से कुछ में धूल, जहरीले धुएं और गैसों का साँस लेना; विकिरण के संपर्क में आना; शोर से होने वाली श्रवण हानि; थकावट, आदि।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, विभिन्न एजेंसियां सतत विकास ढांचे के भीतर काम कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ, मुआवजे और रॉयल्टी के रूप में आर्थिक अवसर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार (जैसे कि एक छोटा व्यवसाय उद्यम), क्षमता निर्माण और अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रदान किए जा सकें (इडेमुडिया और इते, 2006, ओवेन और केम्प, 2015)।

भारत में कोयला खनन की चुनौतियाँ

कोयला भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और इसने देश के तीव्र औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वर्तमान में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कुल कोयला उत्पादन में 8% का योगदान देता है (आईबीएम, 2012)। कोयला मंत्रालय (एमओसी) के विशेषज्ञ उप-समूह ने अनुमान लगाया है कि यदि कोयले की पूरी ज़रूरत स्वदेशी कोयले से पूरी की जाए तो 2006-07 में 330 मीट्रिक टन और 2011-12 में 503 मीट्रिक टन की कमी होगी, और यदि यह कमी बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले के आयात से पूरी की जाए तो 2006-07 में 322 मीट्रिक टन और 2011-12 में 472 मीट्रिक टन की कमी होगी। कोयला उद्योग का कारोबार 340 अरब रुपये का है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.2% है (आईसीआरए, 2006)। विभिन्न शुल्कों और करों के माध्यम से सरकार को योगदान 35 अरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% से अधिक है। कोयला वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा खपत का 55% हिस्सा है और अधिकांश अनुमानों के अनुसार यह आने वाले कई वर्षों तक सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए सबसे व्यवहार्य ईंधन बना रहेगा। भारत में कोयला खनन कुल खनन का 80% हिस्सा है, शेष 20% विभिन्न कच्चे माल जैसे सोना, तांबा, लोहा, सीसा, बॉक्साइट, जस्ता आदि के बीच वितरित किया जाता है। यह भविष्यवाणी की गई है कि अगले 4-5 साल भारत में कोयले की भारी कमी के वर्ष होंगे। मांग में वृद्धि लगभग पूरी तरह से बिजली क्षेत्र द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। शोध से पता चलता है कि ओपन कास्ट खनन ने कई लोगों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित कर दिया है। यह दर्ज किया गया था कि 1950-1991 के दौरान भारत में लगभग 25.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए

खनन उद्योग में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक अवधारणा है जिसके तहत संगठन अपने संचालन के सभी पहलुओं में ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपनी गतिविधियों के प्रभाव की जिम्मेदारी लेकर समाज के हितों की सेवा करते हैं। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" को व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और आर्थिक विकास में योगदान करते हुए कार्यबल और उनके परिवारों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की निरंतर प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित करता है। खनन उद्योग के लिए, सीएसआर समुदायों की विविध मांगों को संतुलित करने और लाभ कमाने की निरंतर आवश्यकता के साथ पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में है (जेनकिंस, 2004)। मौजूदा जवाबदेही तंत्र स्थानीय समुदायों, स्थिरता और स्थायी आजीविका के अवसरों के लिए स्पष्ट कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता बताते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी कंपनी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (कोयला खदानों के मामले में) परियोजनाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में बजट राशि का 80% खर्च करना अनिवार्य है और बजट का 20% उन राज्यों में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए जहां सहायक कंपनियां, यदि कोई हों, काम कर रही हैं। 2013 में, सीआईएल ने सीएसआर गतिविधियों में 950 मिलियन रुपये खर्च किए।

वैश्विक खनन कंपनियों का तर्क है कि कॉर्पोरेट पहल का उद्देश्य समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना (एंग्लो अमेरिकन चिली, 2008), स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना, सामुदायिक विकास और जुड़ाव को बढ़ावा देना (बीएचपी, 2009), और अधिक टिकाऊ समुदायों का निर्माण करना होना चाहिए। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कंपनियां समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेह होती जा रही हैं

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो भूमि के पुनर्वास और मानव आजीविका के लिए आसन्न खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है (हार्फस्ट एंड विर्थ, 2011)। लेखकों ने खदान पर्यावरण संबंधी भूविज्ञान समस्याओं को कम करने के लिए वनस्पति बहाली जैसे इंजीनियरिंग उपायों का सुझाव दिया है (झिगुओ एट अल., 2011)। एक हितधारक के दृष्टिकोण से किए गए एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति सक्रिय रवैया प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण प्रबंधन की सामाजिक स्वीकार्यता को जन्म दे सकता है (मुट्टी, याकोवलेवा, वाज़क्वेज़-ब्रस्ट, एंड डि मार्को, 2012)। खनन और प्रबंधकीय उप-संस्कृति का सह-अस्तित्व खनन उद्योग में सीएसआर के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। फर्मों को प्रबंधन और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के रूप में आंतरिक फर्म संसाधनों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए हितधारकों के साथ विश्वास बनाने में एक गतिशील भूमिका निभा सकते हैं (डोबेले, वेस्टबर्ग, स्टील, और फ्लावर्स, 2014)।

उपरोक्त चर्चा पर्यावरण के रखरखाव के साथ-साथ खदान के आसपास रहने वाले लोगों के लाभ के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक-आर्थिक कारकों को विकसित करने की दिशा में खनन कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों और पहलों को दर्शाती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काफी हद तक खनन उद्योग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हो गया है। अधिकांश फर्म सामुदायिक विकास गतिविधियों में लगी हुई हैं और कुछ ही पर्यावरण बहाली की दिशा में काम कर रही हैं। फिर भी, स्थानीय क्षेत्र की सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है

खनन क्षेत्र में क्षमता निर्माण

खनन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में क्षमता निर्माण पर ज़ोर दिया है। वास्तव में, कॉर्पोरेट खनन क्षेत्र (ICMM, 2005, PDAC, 2014, रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल, 2013) और लैटिन अमेरिका में कार्यरत खनन कंपनियों (एंग्लो अमेरिकन चिली, 2008, BHP, 2009) को दिशा देने वाले स्वैच्छिक वैश्विक मानदंडों ने अपने कॉर्पोरेट विमर्श में क्षमता निर्माण की अवधारणा को अपनाया है। हालाँकि, वैश्विक और कॉर्पोरेट स्तरों पर, क्षमता निर्माण की उनकी अवधारणा स्पष्ट रूप से नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की ओर है।

सामाजिक उत्तरदायित्व पर मार्गदर्शन, ISO. (2010), क्षमता निर्माण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जो समुदायों को सामाजिक और आर्थिक विकास मानकों को प्राप्त करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि क्षमता निर्माण सबसे स्थायी विरासतों में से एक है जो खनन कंपनियां स्थानीय समुदायों को प्रदान कर सकती हैं (ICMM, 2005)। इस धारणा को एक मूल्यवान विरासत भी माना जाता है जो सामुदायिक विकास (रियो टिंटो, 2011) और सहभागिता (बीएचपी, 2009) को बढ़ावा देती है, और स्थायी समुदायों का निर्माण करती है (बैरिक, 2008)। क्षमता निर्माण की ये व्याख्याएँ खनन कंपनियों को क्षमता निर्माण पहलों के प्रमुख प्रदाताओं के रूप में स्थापित करती हैं, और इन पहलों के कार्यान्वयन में अन्य हितधारकों की भागीदारी की उपेक्षा करती हैं। यह ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण, वास्तव में, खनन क्षेत्र को समुदायों पर सार्थक प्रभाव डालने से रोक सकता है (मेट, 2001)। क्षमता निर्माण पहलों में सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने की क्षमता है और इसलिए, खनन कंपनियों के लिए खनन कार्यों के विस्तार में एक SLO प्राप्त करने और बनाए रखने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं (वॉरहर्स्ट, 2001)। ये पहल समुदायों, खनन कंपनियों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए स्थायी परिणाम भी प्रदान कर सकती हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि खनन कंपनियाँ, समुदाय, राष्ट्रीय और स्थानीय

सरकारें, शैक्षणिक संस्थान और खनन क्षेत्र के अन्य संबंधित हितधारक इनके कार्यान्वयन में भाग लें ताकि वे सभी पक्षों के लिए साझा मूल्य का सृजन कर सकें। निस्संदेह, क्षमता निर्माण के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ शामिल हैं, क्योंकि हितधारकों के बीच कई तरह की अंतःक्रियाएँ इस कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकती हैं या बाधित कर सकती हैं। हालाँकि, व्यवहार में क्षमता निर्माण में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद, अनुभवजन्य शोध ने लैटिन अमेरिकी संदर्भों में समुदायों, खनन कंपनियों, स्थानीय सरकारों और खनन संदर्भों में अन्य भूमिका निभाने वालों के लिए मूल्य सृजन हेतु ऐसे दृष्टिकोणों की क्षमता को दर्शाया है (गिब्सन, 2001)।

जहाँ वैश्विक मानदंड और खनन निगम क्षमता निर्माण के लिए एक ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाते हैं, वहीं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के अन्य दृष्टिकोण खनन समुदायों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता के लिए क्षमता निर्माण को एक नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के रूप में लागू करते हैं (अलिज़ार और स्कॉट, 2009, लोज़ा, 2004)। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमता निर्माण को खनन समुदायों के लिए एक स्थायी विरासत माना जाता है (लाहिड़ी-दत्त एट अल., 2014, वेइगा एट अल., 2015)। साहित्य में यह भी कहा गया है कि क्षमता निर्माण पहलों के कार्यान्वयन में कई हितधारकों की भागीदारी शामिल होती है और यह केवल समुदायों पर निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर उनमें शिक्षा और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने और अपने विकास में सक्रिय भागीदार बनने की क्षमता का अभाव होता है (ब्रिज, 1999, लैंज़ी, 2007, मेट, 2001)। ऐसे मामलों में, जहाँ स्थानीय समुदायों की अविकसित परिस्थितियाँ क्षमता निर्माण दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं, सरकारी भागीदारी इन बाधाओं को दूर कर सकती है।

निष्कर्ष

अकादमिक साहित्य में इस बात पर आम सहमति है कि स्थानीय और वैश्विक ताकतों के बीच तनाव ने आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे असंतोष में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में (डी हान और मैक्सवेल, 1998, हैरिसन, 2006, कबीर, 2006)। विनियमन में ढील के बाद बढ़े वैश्विक व्यापार ने नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं या ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) से धातुओं और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग को जन्म दिया है। प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण पर वैश्विक निर्णय लेने से स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि गरीब और स्थानीय समुदायों को अक्सर लगता है कि उन्हें आजीविका के विकल्पों के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है (सुरबोर्ग, 2012)। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और वैश्विक औद्योगिक उत्पादन के बीच का अंतर मुख्य रूप से उत्पादन और वितरण केंद्रों के भौगोलिक फैलाव के कारण हुआ है (अमीन और थ्रिफ्ट, 1992)। संयुक्त उद्यम और अन्य प्रकार के रणनीतिक व्यावसायिक गठबंधन जैसे व्यावसायिक नेटवर्क, बढ़ते पूँजी संचय को सहारा देने के लिए सस्ते श्रम की तलाश करते हैं। हालाँकि, कुछ विद्वानों का तर्क है कि मानव पूँजी अन्य परिसंपत्तियों, जैसे प्राकृतिक संसाधनों (शंकर और शाह, 2003) से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, और उनका तर्क है कि कुशल और शिक्षित कार्यबल वाले क्षेत्र भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालाँकि, खनन क्षेत्र में ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की बढ़ती माँग के कारण इस क्षेत्र ने उन क्षेत्रों में भी अपने कार्यों का विस्तार किया है जो अक्सर खनिजों और धातुओं के भंडार से समृद्ध होते हैं, लेकिन कुशल मानव पूँजी की कमी से जूझते हैं।

सक्रिय खनन क्षेत्रों में कुशल मानव पूँजी की कमी के परिणामस्वरूप, दुनिया भर में जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी शामिल है, जिससे स्थानीय अकुशल मानव पूँजी इन वैश्विक दबावों का मुकाबला करने से वंचित रह जाती है। ये परिस्थितियाँ स्थानीय तनाव पैदा कर रही हैं जो अक्सर कॉर्पोरेट निवेश के लिए खतरा पैदा करते हैं। स्थानीय खनन समुदाय बड़े कॉर्पोरेट मुनाफ़े की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से मिलने वाले सीमांत मुनाफ़े के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं (हिल्सन, 2006, मेट, 2001)। इस स्थिति के कारण खनन कार्यों के निकटवर्ती समुदायों ने बहुराष्ट्रीय खनन निगमों को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में एसएलओ देने से मना कर दिया है।

संदर्भ

1. ए.एम. अलीज़ार, आर. स्कॉट, स्थायी खनन को समर्थन देने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, कैनेडियन माइनिंग जर्नल, 130 (3) (2009), पृ. 24-25
2. पी. बैरिक, निर्वाह खेती से कृषि व्यवसाय तक: सीमाओं से परे कुनकाश्का की कहानी: ज़िम्मेदार खनन पर बैरिक गोल्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट (2008)
3. एस. कार्डेनास, संघर्ष और अनुपालन: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दबाव पर राज्य की प्रतिक्रियाएँ, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय प्रेस, पेन्सिलवेनिया (2011)
4. एन. दास, एन. मिश्रा, ग्रामीण आजीविका के विविध स्रोतों पर कोयला खनन के प्रभाव का आकलन: पश्चिमी ओडिशा, भारत के इब घाटी कोयला क्षेत्र में एक केस स्टडी, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 4 (6) (2015), पृ. 83-88
5. ए.डी. डी हान, एस. मैक्सवेल, संपादकीय: उत्तर और दक्षिण में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार, आईडीएस बुलेटिन, 29 (1) (1998), पृ. 1-9
6. आईबीएम, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 2011, भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (2012)
7. एन. कबीर, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और एमडीजी: एशियाई संदर्भ में 'स्थायी असमानताओं' की चुनौती, आईडीएस बुलेटिन, 37 (3) (2006), पृष्ठ 64-78
8. एम. कुमार, जे. गुप्ता, ए. राधाकृष्णन, झारखंड के रांची और धनबाद जिलों में जनजातियों की डेयरी आधारित आजीविका की स्थिरता, इंडियन जर्नल ऑफ डेयरी साइंसेज, 69 (2) (2015), पृष्ठ 220-225
9. पी.पी. मिश्रा, कोयला खनन और ग्रामीण आजीविका: उड़ीसा के इब घाटी कोयला क्षेत्र का मामला, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44 (44) (2009), पृष्ठ 117-123